भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1761

4 अगस्त, 2023 को उत्तरार्थ

विषय: कपास के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य

1761. श्री एस. कल्याणसुन्दरम:

क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को देश में कपास की कीमतों में भारी गिरावट की जानकारी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) इस समस्या के समाधान के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या सरकार की कपास के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) घोषित करने की कोई योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री

(श्री नरेन्द्र सिंह तोमर)

(क) और (ख): भारत सरकार कृषि लागत और मूल्य आयोग (सीएसीपी) की सिफारिशों, संबंधित राज्य सरकारों और केंद्रीय मंत्रालयों के अभिमतों तथा अन्य संगत कारकों को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक वर्ष कपास के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की घोषणा करती है। एमएसपी आखिल भारतीय भारित औसत उत्पादन लागत पर न्यूनतम 50 प्रतिशत मुनाफा प्रदान करती है।

कपास किसानों को लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने और उनके द्वारा सकंटग्रस्त विक्रय से बचने के लिए, जब कभी कपास की बाजार कीमतें एमएसपी से नीचे गिर जाती है तब एमएसपी के तहत कपास खरीद प्रचालनों हेतु भारत सरकार ने भारतीय कपास निगम (सीसीआई) को केंद्रीय नोडल ऐजेंसी के रूप में नामित किया है। कपास किसानों की सुरक्षा और पहुँच को अधिकतम बनाने के लिए सीसीआई ने वर्तमान कपास मौसम 2022-23 में सभी 11 कपास उत्पादक राज्यों में 400 से अधिक कपास खरीद केंद्र खोले हैं। जुलाई 2023 (28.07.23 तक) के दौरान कपास की औसत थोक मंडी कीमतें 6877 रूपये प्रति क्विंटल थी।

(ग) भारत सरकार ने 7 जून 2023 को कपास के लिए खरीफ विपणन मौसम 2023-24 के लिए मध्यम रेशा कपास हेतु 6620 रुपये प्रति क्विंटल और लंबा रेशा कपास हेतु 7020 रुपये प्रति क्विंटल एमएसपी की घोषणा की है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

******